इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 6 | जनवरी, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ 3
विनियामक के कथन 3
आर्थिक संवेष्टन 4
नयी नियुक्तियाँ 4
विदेशी मुद्रा 5
शब्दावली 5
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 5
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 6
संस्थान समाचार 6
बाजार की खबरें 7
नयी पहलकदमी 8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 तक आयोजित की गई। इसकी मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- रेपो दर 6.5% में कोई परिवर्तन नहीं है।
- स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility) दर बिना बदले 6.25% रहेगी।
- सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility) दर तथा बैंक दर 6.75% बनी रहेगी।

विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर बयान: मुख्य बातें

- 25 बीपीएस प्रत्येक की दो समान किस्तों में नकदी प्रारक्षित (CRR) अनुपात 50 बीपीएस घटाकर 4% कर दिया गया है।
- अधिक पूँजी आगमन को आकर्षित करने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [FCNR (B)] जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा बढ़ा दी है। बैंक अब 1 वर्ष से अधिक से लेकर तीन वर्ष से कम की परिपक्वता वाली नवीन एफसीएनआर (बी) जमाराशियाँ, वैकल्पिक संदर्भ दर में 400 बीपीएस जोड़ कर से अनधिक तथा 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच परिपक्व होने वाली जमाराशियाँ वैकल्पिक संदर्भ दर में 500 बीपीएस जोड़ कर से अनधिक की दरों पर स्वीकार कर सकते हैं।
- एफएक्स-खुदरा प्लेटफॉर्म को भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि इसकी पहुँच का विस्तार हो एवं ग्राहकों का अनुभव बेहतर बने।
- प्रतिभूत मुद्रा बाजार पर आधारित एक नया बेंचमार्क, प्रतिभूत ओवरनाइट रुपया दर (SORR) शुरू किया जाएगा।
- अधिक से अधिक लघु व सीमांत कृषकों को औपचारिक ऋण प्रणाली के दायरे में लाने हेतु, संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण हेतु सीमा प्रति ऋणी 1.6 लाख रुपए से बढ़ा कर 2 लाख रुपए की जाएगी।
- लघु वित्त बैंक अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए पूर्व-स्वीकृत ऋण प्रदान कर सकते हैं।
- वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम मेधा के जिम्मेदार व नीतिपरक कार्यान्वयन हेतु ढांचा (FREE-AI) निर्मित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक एक समिति का गठन करेगी।
- संप्रेषण के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में, पॉडकास्ट सुविधा शुरू की जाएगी।
- म्यूल बैंक खातों की पहचान हेतु म्यूलहंटर एआई नामक एक एआई समाधान लाया जाने वाला है।
- मुक्त विनियम हेतु एक पहल 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' शुरू की जाने वाली है।

निष्क्रिय म्यूचुअल निधियों हेतु सेबी द्वारा एमएफ लाइट (Lite) ढांचे की शुरुआत

निवेशों में विविधता लाने तथा म्यूचुअल निधि उद्योग में नए भागीदारों के प्रवेश को बढ़ावा देने हेतु सेबी ने म्यूचुअल फंड लाइट (Lite) ढांचे की शुरुआत की है। यह ढांचा, 5,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक की प्रबंधनाधीन आस्तियों वाली निष्क्रिय निधियों पर घरेलू इक्विटी सूचकांक के आधार पर सभी सरकारी प्रतिभूतियों पर, ट्रेजरी बिलों पर व राज्य विकास ऋणों (SDLs) पर आधारित घरेलू बाज़ारों को लक्ष्य करने वाली परिपक्वता कर्ज तथा घरेलू स्थिर अवधि निष्क्रिय निधियों पर लागू होगा। इसमें स्वर्ण व रजत ईटीएफ; स्वर्ण या रजत ईटीएफ, ओवरसीज ईटीएफ में निवेश करने वाले निधियों के कोष तथा एकल अंतर्निहित निष्क्रिय निधि वाले निधियों के कोष और पूरी तरह एक ही घरेलू या ओवरसीज सूचकांक में निवेश करने वाले निधियों के कोष को भी शामिल किया गया है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

ऋणदाताओं द्वारा सरकारी कर्ज राहत योजनाओं में उनकी भागीदारी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापक दिशानिर्देश जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं द्वारा सरकारी कर्ज राहत योजनाओं (Debt Relief Scheme or DRS) में उनकी भागीदारी के संबंध में कतिपय दिशानिर्देश जारी किए हैं। विनियमित संस्थाएं अपनी बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर, किसी सरकार द्वारा अधिसूचित

खास डीआरएस में भाग लेने का निर्णय, मौजूदा विनियामक मानदंडों के अधीन ले सकती हैं। कर्जदाताओं को डीआरएस में शामिल किए जाने वाले ऋणियों के विषय में सुनिश्चित कर लेना है ताकि प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी आधारों पर आगे उनका प्रवेश रद्द किए जाने से बचा जा सके। डीआरएस के लाभार्थियों के कर्ज खातों में, कर्जदाताओं द्वारा उपचित किन्तु वसूल न किए गए ब्याज और/या मूलधन के भुगतान को माफ करने, जो या तो डीआरएस के कार्यान्वयन का अंग हो या इसके कार्यान्वयन के बाद हो, को समझौता निपटान माना जाएगा तथा इस पर विवेकपूर्ण बरताव लागू होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को निर्देश: अपरिचालित/अवरुद्ध खातों को शीघ्र कम करें

कई बैंकों में अपरिचालित खातों/अदावी जमाराशियों में वृद्धि से चिंतित होकर, शीर्ष बैंक ने बैंकों को कहा है कि अपरिचालित/अवरुद्ध खातों की संख्या में कमी लाने हेतु शीघ्र कदम उठाएँ तथा ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को सुगमतर एवं कष्टरहित बनाएँ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुझाया है कि बैंक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, मूल से इतर शाखाओं एवं वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया के जरिए निर्बाध केवाईसी अद्यतन संभव कर सकते हैं। अपरिचालित/अवरुद्ध खातों को सक्रिय करने हेतु वे विशेष अभियान आयोजित कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही से बैंकों को ऐसे खातों की रिपोर्ट तिमाही आधार पर संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (SSM) को दक्ष (DAKSH) पोर्टल के माध्यम से भेजनी होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

नेफ्ट, आरटीजीएस हेतु लुक-अप सुविधा बैंकों द्वारा 1 अप्रैल तक लागू कर देनी है

धोखाधड़ी रोकने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाभार्थी खातों में तुरंत सकल निपटान (RTGS) एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणालियों में लुक-अप सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के चलते, उपयोगकर्ता लेनदेन शुरू करने से पूर्व लाभार्थी का नाम देख और इसका सत्यापन कर सकेंगे। विप्रेषकों को यह सुविधा इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से और बैंक शाखाओं में जाकर किए जाने वाले संव्यवहारों हेतु उपलब्ध होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन प्रणालियों के सदस्य बैंकों को यह सुविधा 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का निदेश दिया है। यह सुविधा ग्राहकों को नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।

अन्य पक्ष की अप्लिकेशनों के जरिए पीपीआई से/को यूपीआई भुगतान करने की अनुमति: भारतीय रिज़र्व बैंक

वर्तमान में एक बैंक खाते से/को यूपीआई भुगतान उसी बैंक के अथवा किसी अन्य पक्ष अप्लिकेशन प्रदाता के यूपीआई अप्लिकेशन का उपयोग कर किए जा सकते हैं। तथापि, एक पीपीआई से/को यूपीआई भुगतान पूर्वदत्त भुगतान लिखत (PPI) जारीकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल अप्लिकेशन का उपयोग कर किए जा सकते हैं। यूपीआई भुगतान करने/पाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्ण केवाईसी वाले पीपीआई हेतु अन्य पक्ष अप्लिकेशन के जरिए यूपीआई के उपयोग की अनुमति दे दी है।

विनियामक के कथन

अधिक सुदृढ़ आईबीसी ढांचा, प्रौद्योगिकी का बढ़ा उपयोग कारगर समाधान में मददगार: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) तथा इनसोल (INSOL) इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (IBC) बैंकों के तुलनपत्र को सुदृढ़ करने तथा अपने में निहित संभावनाओं का वित्तीय लेनदारों के दृष्टिकोण से मुख्य हितधारकों हेतु उपयोग करने में किस प्रकार से सहायक है। अपने वक्तव्य में श्री राव ने समग्र समाधान इकोसिस्टम को सुधारने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए: एक- चूक के पीछे कारणों की बेहतर समझ; दो- दिवालापन प्रक्रिया में कुछ कॉर्पोरेट देनदारों द्वारा सहयोग न करने के कारण होने वाली देरी से निपटना; और तीन- मूल्य निर्धारण की जांच करना जिसमें यह शामिल है कि संपार्श्विक का प्रकार मूल्य निर्धारण के समक्ष वसूली को कैसे प्रभावित करता है एवं समाधान में लगने वाले समय एवं मूल्य निर्धारण के परिणाम के बीच संबंध क्या है। उन्होंने ऋणी के आंकड़ों के आधार पर, चूक घटित होने से पहले इसका पूर्वानुमान लगाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग; सुधारात्मक कार्यवाही शीघ्र शुरू करने; संबद्ध पक्षकार या वरीय संव्यवहारों की पहचान करने हेतु संरचित व असंरचित आंकड़ों के विश्लेषण; कर्जदाताओं तथा समाधान पेशेवरों हेतु संसाधनों को बचाने; संवितरण उपरांत ऋण निगरानी में नेमी कार्यों को स्वचालित करने की भी चर्चा की।

जलवायु परिवर्तन जोखिम अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, इसका सामना करने हेतु संसाधनों का प्रवाह आवश्यक है: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) एवं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ (ISAS) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने इस बात की चर्चा की कि जलवायु संबन्धित जोखिम किस प्रकार से परिवारों, कंपनियों तथा राष्ट्रों पर व्यापक आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं जिसका असर उपभोग, उत्पादन व निवेश के तरीकों पर होता है। ऋण, निवेशों तथा अपने खुद के परिचालनों के रूप में कंपनियों का जलवायु जोखिम से सामना वित्तीय संस्थानों को ऋण, बाजार, नकदी एवं परिचालन जोखिमों की पारंपरिक जोखिम श्रेणियों के जरिए प्रभावित करता है।

व्यावहारिक दृष्टिकोण, अग्रणी जिला प्रबंधकों का अनुभव ऋण योजनाओं को अधिक समावेशी बना सकता है भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

महाराष्ट्र के अग्रणी जिला प्रबंधकों (Lead District Managers or LDM) के हाल के एक सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) में से करीब आधे तक औपचारिक ऋण की पहुँच अब तक नहीं हो सकी है, लघु व सीमांत कृषकों (Small and Marginal Farmers) के एक बड़े हिस्से को बैंक वित्त नहीं मिल रहा और बहुत सारे एमएसएमई विशेषकर वे जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, वित्तीय क्षेत्र में अल्प सेवित हैं। इसलिए उन्होंने इन समूहों की ऋण जरूरतों को उपयुक्त संभावना संबद्ध ऋण योजनाओं के जरिए तथा खंड व जिला स्तरीय ऋण कार्यनीतियों में पूरा करने हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण जिसमें अग्रणी जिला प्रबंधकों का जमीनी अनुभव शामिल हो, अपनाने का सुझाव दिया। संक्षेपाक्षर LDM के लिए भिन्न अर्थ देते हुए श्री स्वामीनाथन ने तीन गुण निर्दिष्ट किए, जो हैं- (L)iaison, (D)esigning तथा Development एवं (M)onitoring और Motivating। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि अग्रणी जिला प्रबंधकों को डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, नवंबर 2024 की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में अप्रैल-अक्तूबर 2024 से वर्षानुवर्ष 4% की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 7.1% की वृद्धि के साथ सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6% की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- मुख्यत: वनस्पति मुद्रास्फीति में गिरावट के चलते नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति अक्तूबर के 10.9% से घटकर 9% हो गई, हालांकि यह दो अंकों में बनी हुई है।
- वित्तवर्ष 25 के प्रथम आठ महीनों में 7.6% की बढ़त के साथ भारत के समग्र निर्यात (वस्तु एवं सेवा) में अच्छी वृद्धि हुई।
- अप्रैल-नवंबर 2024 में वस्तु निर्यात में 8.3% की वृद्धि हुई जिसका बड़ा कारण गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण आयातों का बढ़ जाना है।
- नवंबर 2024 के उत्तरार्ध में निवल एफपीआई अंतर्वाह 967.1 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जबकि माह के पूर्वार्ध में 3218.2 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ था।
- वित्तवर्ष 25 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को पुनर्जीवन मिला, यह वित्तवर्ष 24 के प्रथम सात महीनों के 42.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर वित्तवर्ष 25 की इसी अवधि में 48.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जो वर्षानुवर्ष 15.5%.की वृद्धि है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री संजय मल्होत्रा	गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री रामा मोहन राव अमारा	प्रबंध निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार एवं प्रौद्योगिकी (आईबी, जीएम व आईटी), भारतीय स्टेट बैंक
श्री अमितव चटर्जी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 दिसंबर, 2024 के दिन करोड रुपए	27 दिसंबर, 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डॉलर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5476869	640279	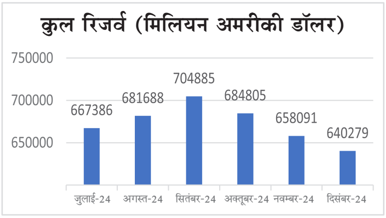
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4721047	551921	
1.2 सोना	566843	66268	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	152881	17873	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	36097	4217	नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

31 दिसंबर 2024 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) हेतु वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) की आधार दरें-जनवरी 2025 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	4.46
जीबीपी	4.7
यूरो	2.916
जापानी येन	0.227
कनाडाई डॉलर	3.3100
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	0.455916

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डॉलर	4.25
स्वीडिस क्रोन	2.622
सिंगापुर डॉलर	2.5512
हांगकांग डॉलर	5.04674
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	2.5860

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

निष्क्रिय निधियाँ

निष्क्रिय निधियों में निधि प्रबंधक की निष्क्रिय भूमिका होती है क्योंकि शेयर चुनने/खरीदने, रोके रखने, बेचने का निर्णय बेंचमार्क इंडेक्स से चालित होता है और निधि प्रबंधक/डीलर को इसे न्यूनतम ट्रैकिंग अशुद्धि के साथ दुहराना होता है। वे ऐसा पोर्टफोलियो रखते हैं जो बताए गए सूचकांक या बेंचमार्क अर्थात इंडेक्स फंड तथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) को दुहराए।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि (CDMDF)

इस निधि को सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमावली, 2012 (एआईएफ विनियमावली) के अध्याय III-सी के तहत स्थापित किया गया है। यह निधि संकट के समय में कॉर्पोरेट ऋण बाजार में भागीदारों के बीच विश्वास लाने हेतु, निवेश श्रेणी कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के क्रय के लिए अवलंब सुविधा के रूप में कार्य करने तथा बाजार संकट के समय में सक्रियन हेतु स्थायी संस्थागत ढांचा निर्मित कर सामान्यत: द्वितीयक बाज़ार तरलता बढ़ाने के लिए है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी 2025 में संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे-

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
बैंकों/वित्तीय संस्थानों में जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	13-15 जनवरी 2025	वर्चुअल
शाखा प्रबंधकों हेतु नेतृत्व तथा सॉफ्ट स्किल विकास पर कार्यक्रम	15-17 जनवरी 2025	लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, कुर्ला (प) मुंबई
तुलन पत्र अध्ययन व अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	15-17 जनवरी 2025	
बैंकों व वित्तीय संस्थानों हेतु साइबर जोखिम प्रबंधन और आईटी सुरक्षा पर कार्यक्रम	16-17 जनवरी 2025	
कासा बढ़ाने हेतु एक साधन कारगर शिकायत समाधान प्रक्रियाओं पर कार्यक्रम	17-18 जनवरी 2025	
ऋण निगरानी और वसूली पर कार्यक्रम	20-22 जनवरी 2025	
ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पर कार्यक्रम	21-22 जनवरी 2025	
बैंकों व वित्तीय संस्थानों में अनुशासन प्रबंधन, जांच तथा अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रिया पर कार्यक्रम	21-23 जनवरी 2025	वर्चुअल
संधारणीयता हेतु नीतिपरक बैंकिंग पर कार्यक्रम	22 जनवरी 2025	
प्रभावी अनुपालन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा पर कार्यक्रम	27-28 जनवरी 2025	
बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षकों हेतु कार्यक्रम	28-29 जनवरी 2025	
बिजनेस अनलिटिक्स, मशीन लर्निंग एवं कृत्रिम मेधा तथा बैंकों में इनके प्रभाव पर कार्यक्रम	28-30 जनवरी 2025	
उन्नत ऋण प्रबंधन पर कार्यक्रम	28-30 जनवरी 2025	
आईटी एवं साइबर सुरक्षा-ढांचे, आईटी जोखिम प्रबंधंन तथा साइबर अपराध रोकने पर कार्यक्रम	30-31 जनवरी 2025	आईआईबीएफ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, दक्षिण अंचल, 94, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, वड़पलनी, चेन्नई-600026

संस्थान समाचार

अंतर-बैंक क्विज प्रतियोगिता-बैंकिंग चाणक्य का 4था संस्करण

संस्थान ने अंतर-बैंक क्विज प्रतियोगिता-बैंकिंग चाणक्य-2024, 21 नवंबर 2024 से शुरू की है। प्रारम्भिक चक्र में इसमें अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न बैंकों से 3783 टीमों ने भागीदारी की। क्विज प्रतियोगिता में राष्ट्रीय चैंपियन के लिए एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार रखा गया है। राष्ट्रीय फाइनल 18 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाने वाला है।

आईआईबीएफ द्वारा सूक्ष्म व व्यापक शोध 2024-25 हेतु पेपर/प्रस्ताव आमंत्रित

सूक्ष्म शोध, संस्थान के आजीवन सदस्यों (बैंकरों) हेतु एक प्रकार की निबंध प्रतियोगिता है जिसमें उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों पर अपनी मौलिक सोच, विचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करना होता है। व्यापक शोध में, संस्थान व्यावहारिक शोध को प्रोत्साहित करता है जिसमें शोधकर्ता डेटा (प्राथमिक/द्वितीयक) के जरिए अपनी परिकल्पना को परख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है। अधिक विवरण www.iibf.org.in पर है।

आईआईबीएफ द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु डायमंड जुबिली तथा सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

संस्थान ने डायमंड जुबिली तथा सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थियों को भारत या विदेश में बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है। विस्तृत विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें ।

आईआईबीएफ-पीडीसी उत्तरी जोन द्वारा 2-6 दिसंबर 2024 तक नेतृत्व एवं सॉफ्ट स्किल्स विकास पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) का आयोजन

आईआईबीएफ-पीडीसी उत्तरी जोन ने नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार नेपाल के बीएफएसआई पेशेवरों हेतु नेतृत्व एवं सॉफ्ट स्किल्स विकास पर केंद्रित प्रबंधन विकास कार्यक्रम संचालित किया। कार्यक्रम में रणनीतिक एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व, भावनात्मक बुद्धिमता, कारगर संप्रेषण, बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटीकरण की यात्रा तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों यथा डिजिटल बैंकिंग व साइबर सुरक्षा, अंतर्व्यैक्तिक संबंध, सहयोग तथा टीमवर्क पर ज़ोर दिया गया।

नेपाल के सूक्ष्म वित्त संस्थानों के कार्यपालकों हेतु आईआईबीएफ-पीडीसी उत्तर जोन द्वारा 17-20 दिसंबर 2024 तक 4 दिवसीय एमडीपी का आयोजन

आईआईबीएफ-पीडीसी उत्तर जोन ने नेपाल के सूक्ष्म वित्त संस्थानों के वरिष्ठ कार्यपालकों, जिन्हें नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, नेपाल द्वारा नामित किया गया था, के लिए 4 दिवसीय विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सा-धन के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ श्री जिजी मम्मान ने किया। कार्यक्रम में भारत में प्रदत्त सूक्ष्म ऋण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था और इसके साथ नेपाल में स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। मुख्य विषय थे-सूक्ष्म ऋणदाताओं के प्रकार, वित्तीय समावेशन तथा सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) की लाभप्रदता का आकलन, कारगर वसूली प्रबंधन, ऋण चुकौती में देरी के मामलों से निपटने व ऐसे मामलों में को कम करने हेतु कार्यनीतियाँ, सूक्ष्म वित्त में ग्राहक सुरक्षा, नेतृत्व, अभिप्रेरणा एवं निष्पादन में सुधार।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

जनवरी–मार्च 2025 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'साइबर धोखाधड़ी प्रबंधन' होगा।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामकों द्वारा सूचित हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्र में शामिल करने के उद्देश्य से विनियामक(कों) द्वारा केवल 30 जून 2024 तक जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग जगत की इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

बाजार की खबरें

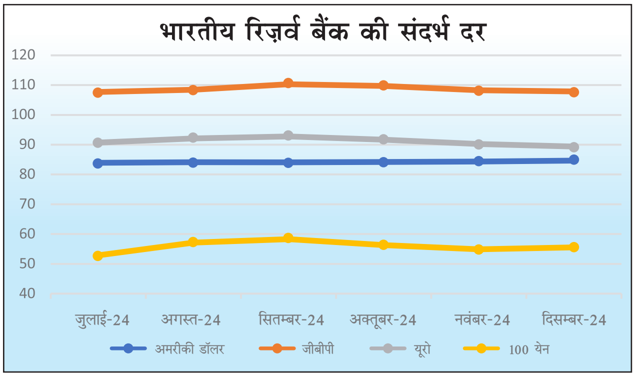

स्रोत: एफबीआईएल

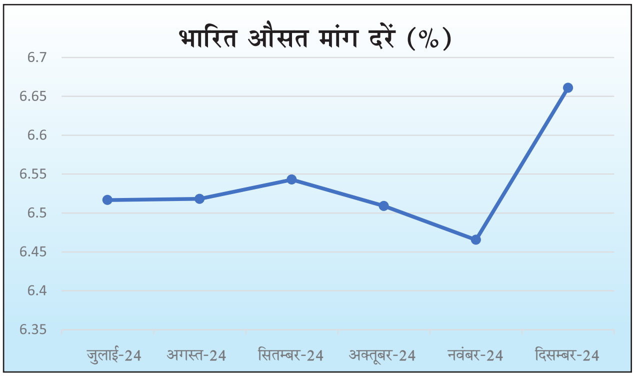

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

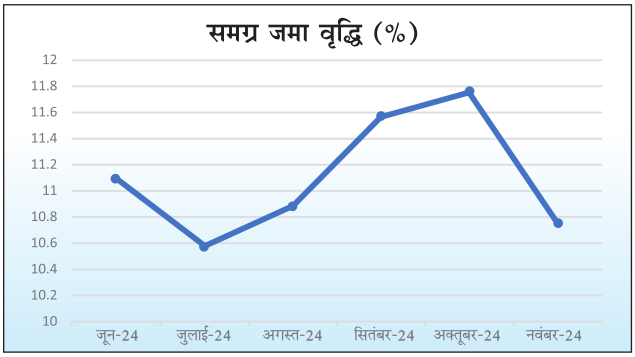

स्रोतः अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर, 2024

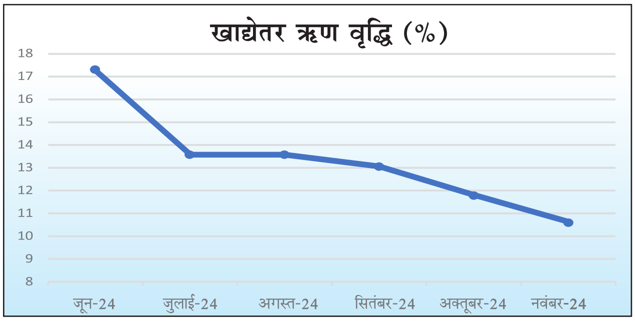

स्रोतः अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर, 2024

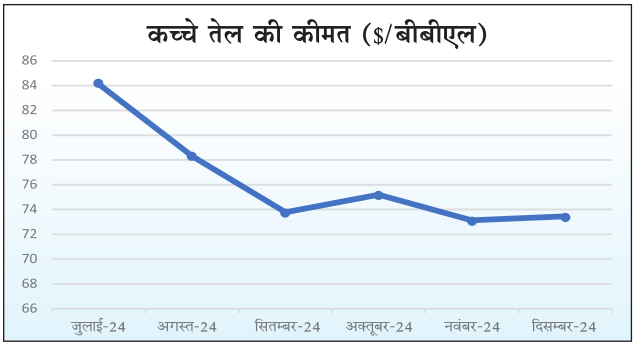

स्रोतः पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

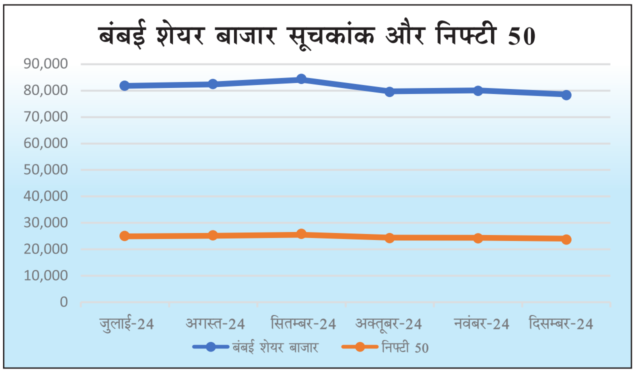

स्रोतः बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

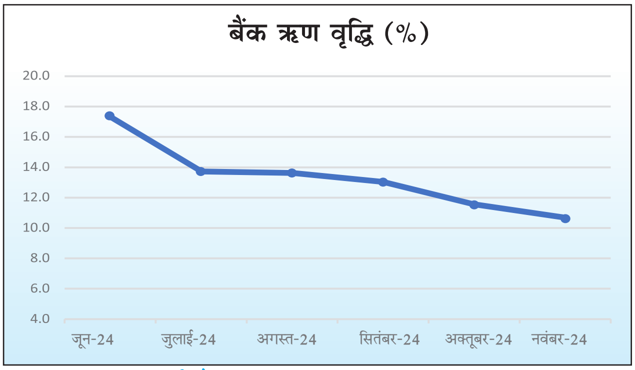

स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक

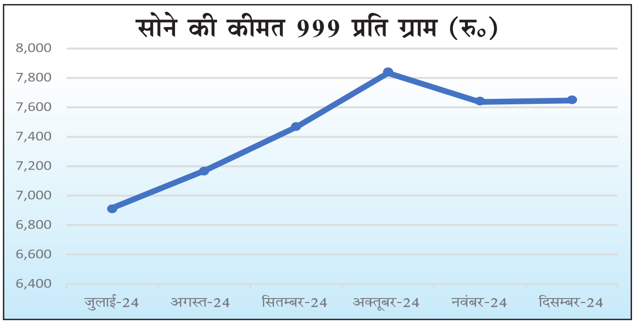

स्रोतः गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in